>

Title: Need to release funds to Uttar Pradesh under the Accelerated Irrigation Benefits Programme.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत सरकार की त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत, सिंचाई की वृहद और छोटी-बड़ी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार धन देती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से ऐसी परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। जहां पानी की व्यवस्था और साधन है। लेकिन इन छोटी-बड़ी परियोजनाओं को धन न मिलने से ठीक ढंग से कार्य नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की बाणसागर परियोजना है, जो अधूरी पड़ी है और अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार बरसाती नदियां होती हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में नाद नदी है। अगर इस नदी पर इस योजना के अंतर्गत चेक-डैम बना दिए जाएं तो नदी के किनारे जो दर्जनों गांव हैं, उनको सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे और पानी के रिचार्ज का भी काम हो जाएगा। इस योजना के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में दो बड़ी परियोजनाएं हैं - नारायणपुर पंप कैनाल और भूपौली पंप कैनाल। जहां पर संसाधन और पैसे न होने के कारण परियोजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा रहा है और पानी हेड से टेल तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। जनपद चंदौली के पूर्वी महाइच और उत्तर नर्वण के किसान लगातार इस पानी के लिए संघर्ष करते चले आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसी प्रकार शारदा नहर है, जो कि 250-300 किलोमीटर तक लंबी है, जिसका पानी गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, भदोही और इलाहाबाद तक पहुंचता है। बनारस में उसकी दो-तीन नहरें हैं। जिनका रख-रखाव, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण न होने से पानी या तो बह जाता है या टेल तक नहीं पहुंच पाता है। यह परियोजना भी अधूरी पड़ी हुई है। दो-तीन बिंदु और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। त्वरित सिंचाई लाभ योजना इसीलिए बनाई गई थी जिससे हम पानी का ठीक से उपयोग कर सकें और जहां भी किसानों को पानी जरूरत हो, वहां पानी दे सकें। कभी-कभी ऐसा होता है कि भारी वर्षा होने से और ड्रेनों की खुदाई न होने से हजारों हेक्टेयर जमीनें और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में धूस-नोनार ड्रेन है, वह परियोजना भारत सरकार के पास पड़ी हुई है। उस पर धन न मिलने से वह अधूरी पड़ी हुई है। इसी प्रकार जमनिया पंप कैनाल, गाजीपुर से 38 करोड़ की एक परियोजना बनी है, जो धन के अभाव में झूल रही है। अगर उस परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत पूरा करा दिया जाए तो उससे जनपद चंदौली के पूर्वी और उत्तरी किसानों को लाभ मिल जाएगा। इस प्रकार जो हमारी दूसरी परियोजनाएं है, उन परियोजनाओं को काम मिल जाएगा। ...(व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने एक मांग की है, प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी भेजा है, एक प्रस्ताव भेजा है। दो हजार करोड़ रूपये का एक प्रस्ताव इन परियोजनाओं के लिए भेजा गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार त्वरित सिंचाई लाभ योजना को लागू करे और उत्तर प्रदेश को धन मुहैया कराये। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।